

# HRA AN USIUA The Gazette of India

संसाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] No. 405] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2008/कार्तिक 21, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2008/KARTIKA 21, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय) जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2008

विषय : कोरिया जन गण से फॉस्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों तथा सांद्रणों ( कृषि / उर्वरक ग्रेड को छोड़कर ) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 14/7/2007-डीजीएडी.—यत: मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा तथा मै. सोलारिस केमटैक लि. करवर (जिन्हें एतद्पश्चात् आवेदक कहा जाएगा) ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिन्हें एतद्पश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने कोरिया जन गण के (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फॉस्फोरिक एसिड (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के सभी ग्रेडों तथा सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के कथित पाटन का आरोप लगाया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

2. और जबिक प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षित तथा पाटन एवं क्षित के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतद्द्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षित को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षित की जांच प्रारम्भ करते हैं।

## विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

- 3. विचाराधीन उत्पाद कोरिया जन गण के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेडों एवं सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) वाला फॉस्फोरिक एसिड है ।
- 4. फॉस्फोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन है जिसे सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नेशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट इत्यादि के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाता है। संबद्ध वस्तु को भेषजीय उपयोगों, पेय पदार्थों, बीज प्रसंस्करण, चीनी के शिंद के शुद्धिकरण तथा चीनी के प्रसंस्करण, खाद्य फॉस्फेट विनिर्माण इत्यादि हेतु भी उपयोग में लाया जाता है।

- 5. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2809.20 के तहत एवं भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार क्रम.सं. 2809.2020 के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, सीमाशुल्क एवं आई टी सी एच एस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं ।
- 6. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं कोरिया जन गण के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है और वे दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपर्युक्त नियमावली के अर्थों के भीतर संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

# घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मै0 गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स ति0 बड़ौदा तथा मै0 सोलारिस केमटैक लि0 करवर द्वारा संयुक्त रूप से घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) तथा नियम 5 (3)(क) के अनुसार आवेदकों के पास घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच हेतु मामला दायर करने का अधिकार है।

# शामिल देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया जन गण है।

#### सामान्य मूल्य

9. आवेदकों ने दावा किया है कि कोरिया जन गण में उत्पाद को खुदरा स्तर पर बेचा नहीं जाता है और इसलिए वे कोरिया जन गण के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत के विषय में कोई सूचना/साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं । अतः आवेदकों ने उचित लाभ मार्जिन सहित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर विचार किया था और प्रारंभिक जांच हेतु भी प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है ।

# निर्यात कीमत

10. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसूचना प्रणाली (आई बी आई एस), मुम्बई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया गया है । निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैण्डलिंग एवं पत्तन प्रभारों इत्यादि के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं हेतु आवेदकों द्वारा दावा किए गए निर्यात कीमतों के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं ।

## पाटन मार्जिन

11. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

## क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों ने इस बात के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि पाटित आयातों की बढ़ती मात्रा, कीमत कटौती तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक गिरावट के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षिति हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदकों को वास्तविक क्षति हो रही है।

# जांच अवधि (पी ओ आई)

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 (12 महीने) तक की है । तथापि क्षति जांच अवधि में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल होगी ।

## सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों तथा घरेलू उद्योग को संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र तथा पद्धित में प्रस्तुत करने हेतु अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग पाटनरोधी एवं संबद्ध शुक्क महानिदेशालय (डी जी ए डी) कमरा सं. 240, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011

# समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

## सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

- 16. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।
- 17. सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रस्तुत गोपनीय सूचना के साथ नियम 7(2) के संदर्भ में उसका एक गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करेंगे।
- 18. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को उचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2008

Subject: Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agricultural/Fertilizer Grade) from Korea RP.

- F. No. 14/7/2007-DGAD.—Whereas M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Baroda and M/s Solaris Chemtach Limited, Karwar (hereinafter referred to as applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules) alleging dumping of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations Agriculture/Fertilizer Grade) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as subject country) and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of antidumping duties.
- 2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### Product under consideration and Like Article

3. The product under consideration is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP.

- 4. Phosphoric Acid is an inorganic chemical used for the production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, etc. The subject goods are also being used in Pharmaceutical applications, beverages, seed processing, sugar juice clarification and sugar refining, food phosphate manufacturing, etc.
- 5. The product is classified under Customs Tariff heading 2809.20 and at SI. No. 2809.20 20 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- 6. The applicants have claimed that goods produced by them are like articles to the subject goods originating in or exported from Korea RP. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and those exported from subject country and the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the goods produced by the domestic industry are being treated as Like Article to the product imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

## **Domestic Industry**

7. The application has been jointly filed by M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited — Baroda and M/s Solaris Chemtach Limited — Karwar on behalf of the Domestic Industry. As per evidence available, applicants have the standing to file the case for Anti Dumping Investigations on behalf of the domestic industry as per Rule 2 (b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

#### Countries involved:

8. The Country involved in the present investigation is Korea RP.

#### **Normal Value**

9. The applicants have claimed that the product is not sold at retail level in Korea RP and therefore, they have not been able to get any information/evidence of price of subject goods in domestic market of Korea RP. The applicants therefore claimed Normal Value based on cost of production of the domestic industry including reasonable profit margin. The Authority has prima facie considered the Normal Value of the subject goods in the subject country on the basis of constructed values as made available by the applicants as per facts available and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

#### **Export Price**

10. The export prices have been claimed on the basis of data obtained from International Business Information System (IBIS), Mumbai. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland

4398 GIJ/08-2

transportation, port handling and port charges etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices, claimed by the applicants for the subject goods from the subject country.

## **Dumping Margin**

11. There is sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export prices indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject country.

## **Injury and Causal Link**

12. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting and substantial decline in performance of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the material injury being suffered by the applicants caused by dumped imports from subject country.

### Period of Investigation (POI):

13. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2007 to 31st March 2008 (12 months). The injury investigation period will however, cover the period 2004-05, 2005-06, 2006-07 and the Period of Investigation.

#### Submission of information:

14. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

#### Time limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received

is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

## Inspection of public file

- 16. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.
- 17. All interested parties shall provide a Confidential and Non-confidential summary in terms of rule 7(2) for the confidential information provided as per rule 7 (1) of the Rues supra.
- 18. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority